



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 21]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 23, 1970 (ज्येष्ठ 2, 1892)

No. 21]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 23, 1970 (JYAISTHA 2, 1892)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 4

## (PART III—SECTION 4)

विभिन्न निकायों द्वारा जारी की गई विभिन्न अधिसूचनाएं जिसमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं  
(Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies)

स्टेट बैंक आफ इंडिया

केन्द्रीय कार्यालय

बम्बई, दिनांक 9 मई 1970

स्टेट बैंक आफ इंडिया (सहायक बैंक) ऐक्ट 1959, सेक्शन 29(1) के अनुसार स्टेट बैंक आफ इंडिया ने स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्रा के निदेशक-मण्डल के साथ विचार विनिमय करने के पश्चात् तथा रिजर्व बैंक आफ इंडिया की स्वीकृति लेकर, श्री बी० के० चटर्जी को स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्रा के जनरल मैनेजर के पद पर दिनांक 3 मई, 1970 से 2 मई, 1973 (दोनों दिन सम्मिलित) तक नियुक्त किया है।

टी० आर० बरदाचारी,  
प्रबन्ध निदेशक

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

(औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 (1948 का xv)  
के अधीन नियमित)

(भारतीय औद्योगिक वित्त निगम कर्मचारी भविष्य निधि  
विनियमों में संशोधन)

नई दिल्ली, दिनांक 11 मई 1970

संख्या 2/70—औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948  
(1948 का xv) की धारा 43(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का

M7981/70

प्रयोग करते हुये, संचालक बोर्ड ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से परामर्श करने के बाद तथा भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारतीय औद्योगिक वित्त निगम कर्मचारी भविष्य निधि विनियमों में निम्नलिखित संशोधन किये हैं :—

## विनियम 2—

चौथी पंक्ति में “अधिकारियों” शब्द के बाद “तथा पर्यवेक्षक अधिकारियों” शब्द जोड़ दिये जायेंगे और इसी पंक्ति में से अधिकारियों शब्द हटा दिया जायेगा, जिसका प्रतिस्थापन “,” से होगा। “लिपिक वर्ग का एक” के बाद “अधीन कर्मचारी वर्ग का एक” शब्द जोड़ दिये जायेंगे।

## विनियम 5 : उप-खंड (1)

“वरिष्ठ सेवा में तथा उपाश्रित सेवा में प्रत्येक कर्मचारी जिसका वेतन 30 रुपये अथवा अधिक हो” शब्द हटा दिये जायेंगे। आगे विनियम का दूसरा वाक्य “उपाश्रित सेवा में एक कर्मचारी 30 रुपये प्रतिमास से कम लेता हो, स्वेच्छा से अभिदान कर सकता है” भी पूरा हटा दिया जायेगा।

## उपखण्ड (III)

वर्तमान उप-खण्ड (III) के लिए निम्नलिखित उप-खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा :

(क) यदि प्रबन्धक स्वीकृति दें तो एक अस्थायी कर्मचारी जो किसी अन्य भविष्य निधि में अभिदान नहीं कर रहा हो, वह निधि में अभिदान कर सकता है।

(ख) कोई भी अन्य व्यक्ति जिसे निगम से नैमित्तिक पारिश्रमिक से अन्य पारिश्रमिक मिलता है, तो वह प्रबन्धकों की स्वीकृति से अभिदान कर सकता है।

परन्तु यह है कि ऐसे व्यक्ति के निधि खाते में कोई राशि जमा है और वह विनियम 14 की शर्तों के अनुसार देय हो गई है, तो कुछ विशेष मामलों को छोड़कर राशि प्रबन्धकों की स्वीकृति से उसके खाते में तब तक जमा रहेगी जब तक वह निगम से नैमित्तिक पारिश्रमिक से अन्य पारिश्रमिक प्राप्त करता रहेगा। विनियम 13 पर विपरीत प्रभाव डाले बिना इस राशि पर व्याज जमा होता रहेगा।

#### विनियम-5क

विनियम 5 के बाद निम्नलिखित एक नया विनियम 5—क जोड़ा जायेगा :—

“कोई कर्मचारी प्रबन्धकों की स्वीकृति से यदि विनियम 5 के अनुसार अभिदान करता है अथवा अभिदान करने की स्वीकृति लेता है तो वह अपने पूर्व नियोक्ता अथवा नियोक्ताओं से प्राप्त कोई राशि अथवा सेवाओं के लिये प्राप्त निवृत्ति लाभ को अपने निधि खाते में जमा करा सकता है।

परन्तु यह कि निगम को निधि में जमा की गई ऐसी किसी राशि के लिए कोई अंशदान न करना पड़े।”

#### विनियम-6

विनियम की छठी पंक्ति में “आठ आना” शब्द “आधा रुपया” शब्दों से प्रतिस्थापित होंगे।

#### विनियम 8

इस विनियम के स्पष्टीकरण का मसौदा पुनः बनाया जायेगा जो निम्न प्रकार से होगा :—

“स्पष्टीकरण : इस विनियम और विनियम 6 के लिए कर्मचारी द्वारा ली गई राशि जो “वेतन” होगी—

- (i) उसके पद का स्वीकृत वेतन जो उसे बाद में अथवा स्थानापन्न की हैसियत से अथवा उसके कैंडर स्थिति के अनुसार वेतन जिसे वह प्राप्त करने का अधिकारी है;
- (ii) समुद्रपार वेतन, विशेष वेतन, और वैयक्तिक वेतन;
- (iii) कोई अन्य परिलब्धियाँ, जिन्हें बोर्ड ने विशेषतः वेतन के रूप में स्वीकृत किया हो।”

#### विनियम 9

आठवीं पंक्ति में आये शब्द “एक आना” का “पैसा” शब्द से प्रतिस्थापन किया जायेगा।

#### विनियम 11—

(क) उप-विनियम 1 (क) के वर्तमान उप-खण्ड (I), (II) और (III) निम्नलिखित खण्डों से प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

- (i) अभिदाता अथवा उस पर वास्तविक रूप से आश्रित व्यक्ति की बीमारी, परिरोध अथवा विकलांगता जहाँ जरूरी हो यात्रा व्यय सहित खर्चों की अदायगी के लिए;

(ii) अभिदाता अथवा उस पर वास्तविक रूप से आश्रित व्यक्ति की निम्न मामलों में उच्च शिक्षा पर व्यय के लिए, अर्थात्—

(क) हाई स्कूल स्तर के बाद भारत से बाहर शैक्षणिक तकनीकी, व्यावसायिक अथवा वृत्तिक पाठ्यक्रमों के लिए; और

(ख) हाई स्कूल के बाद भारत में किसी अन्य डाक्टरी, इंजीनियरी अथवा अन्य तकनीकी अथवा विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए, परन्तु यह कि पाठ्यक्रम कम तीन वर्षों से कम न हो;

(iii) अभिदाता अथवा उसकी सन्तान अथवा उस पर वास्तविक रूप से आश्रित व्यक्ति के विवाह, अनुष्ठान पर व्यय जो उसके स्तर अनुकूल तथा सामाजिक प्रथा अनुसार अनिवार्य हो;

परन्तु यह कि वास्तव में आश्रित होने की शर्त पुत्र अथवा पुत्री के मामले में अथवा जब अग्रिम की जरूरत अभिदाता के माता-पिता के दाहसंस्कार पर व्यय के लिए हो, लागू नहीं होगी;

(iv) अभिदाता के द्वारा उसके पदीय कर्तव्य के सम्बन्ध में लगाये गये आरोपों से दोष मुक्ति पाने के लिए की गई वैधिक कार्यवाही पर व्यय के लिए इस मामले में यह अग्रिम निगम के अन्य किसी स्रोत के अतिरिक्त होगा।

परन्तु यह कि इस उप-खण्ड के अधीन उस अभिदाता को अग्रिम नहीं मिलेगा, जो निगम के विरुद्ध किसी न्यायालय में पदीय कर्तव्य से असम्बन्धित अथवा नौकरी की शर्तों अथवा उस पर लगाये गये दण्ड के मामले में कानूनी कार्यवाही कर रहा हो;

(v) किसी भी न्यायालय में निगम द्वारा अभियोग चलाने पर अभिदाता की आत्म-रक्षा पर व्यय के लिए;

(vi) किसी अन्य खर्च अथवा देयता जो निगम की दृष्टि में अप्रत्याशित और विशेष तथा अभिदाता के सामान्य साधनों से बाहर हो, को पूरा करने के लिए;

(ख) विनियम 11 के उप-विनियम I (ख) का खण्ड (II) निम्नलिखित खण्ड से प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

“पूर्व अग्रिम की अन्तिम अदायगी तक मंजूर”

(ग) विनियम 11 के उप-विनियम 2(क) के पहले वाक्य की समाप्ति पर संख्या “24” के बाद निम्नलिखित परन्तु जोड़ दिया जायेगा :—

परन्तु यह कि विशेष मामलों में उप-विनियम (I) के खण्ड (ख) के अधीन जहाँ अग्रिम तीन मास के वेतन से अधिक हो तो निगम किस्तों की संख्या 24 से अधिक निर्धारित कर सकती है जो किसी भी वृत्ति में 36 से ज्यादा न होंगी।

**विनियम 11—क**

विनियम 11 के बाद निम्नलिखित (1), (2) और (3) खण्डों वाला एक नया विनियम जोड़ दिया जायेगा :—

- “(1) निगम के विवेक से कुछ शर्तों तथा सीमाओं के अधीन अभिदाता के निवेदन पर निधि से अपने तथा अपने पर आश्रित व्यक्ति के लिए उचित मकान अथवा परिसर प्राप्त करने के बाद एकमात्र उद्देश्य से सहकारी हाऊसिंग समिति के शेयर खरीदने अथवा कोई अन्य जमा करने अथवा जमानत के तौर पर रुपया जमा कराने के लिए।
- (2) इस विनियम के अधीन अग्रिम की कर्मचारी के सेवा-काल में केवल एक ही बार अनुमति मिलेगी, जो उसकी निधि में ब्याज सहित जमा रकम अथवा वास्तविक उद्देश्य के लिए जरूरी, जो भी कम हो, से ज्यादा न होगी।
- (3) इस विनियम के अधीन अग्रिम की बसूली की किस्त, राशि निगम द्वारा निर्धारित की जायेगी, पर किसी मामले में भी किस्तों की संख्या 120 से अधिक नहीं होगी। अभिदाता स्वेच्छा से एक मास में एक से अधिक किस्त दे सकता है, परन्तु किस्त पूरे रुपयों में होगी।”

**विनियम 12**

(क) वर्तमान विनियम की संख्या उप-विनियम (1) हो जायेगी और विनियम 12 के उप-विनियम (1) के बाद निम्नलिखित एक नया उप-विनियम (2) जोड़ दिया जायेगा :—

- “(2) जहां उप-विनियम 1(ख) के अधीन अभिदान की गई राशि में से ऐसी बीमा पालिसी जो बंधित है अथवा अदा कर दी गई, बीमा किस्त अदायगी के लिए पालिसी निगम द्वारा लगाई शर्तों के अधीन, यदि बीमाधारी से कुछ बकाया हो, को वसूल करने के लिये, निगम को परिवर्तित कर दी जायेगी।”

**विनियम 13**

वर्तमान विनियम निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

“अभिदाता के खाते के जमा सभी राशि पर अदायगी किये जाने वाले मास से पहले मास तक अथवा जिस मास में राशि देय हो, उससे पहली छमाही की समाप्ति तक, जो भी कम हो, ब्याज देय होगा।

परन्तु यह कि जब निगम अभिदाता अथवा उसके नामित को राशि अदा करने की तिथि सूचित कर देती है तो इसके बाद कोई ब्याज अदा नहीं किया जायेगा।”

**विनियम 14**

(क) वर्तमान विनियम की संख्या उप-विनियम (1) कर दी जायेगी और इस प्रकार संख्या परिवर्तित उप-विनियम (1) निम्नलिखित उप-विनियम से स्थानान्तरित हो जायेगा :—

(1) अभिदाता के खाते में जमा रकम उसकी सेवा की समाप्ति अथवा मृत्यु हो जाने पर देय हो जायेगी

“परन्तु यह कि अभिदाता निवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चाहे तो निधि में से अपने अभिदान तथा उस पर ब्याज के बराबर रकम निकाल सकता है :—

परन्तु यह भी कि अभिदाता अथवा अन्य कोई व्यक्ति जो विनियम 5 के खण्ड (III) के अधीन अभिदान करता है, बीस वर्ष सेवा पूरी करने के बाद किसी समय अथवा सेवानिवृत्ति से 10 वर्ष तुरन्त पहले अथवा उसके कार्यकाल की विशिष्ट अवधि के बाद, निगम के विवेक से, विनियम 14—क में से उल्लिखित राशि तक, उप-विनियम (2), (3) और (4) में वर्णित उद्देश्यों, शर्तों के अनुसार निधि में से धन निकाल सकता है।”

परन्तु आगे यह कि यदि अधिकारियों के मामले में बोर्ड और अन्य के मामले में अध्यक्ष निम्नलिखित राशि काट कर निगम को अदा करने का निदेश करे :—

- (क) निगम के प्रति अभिदाता की देयता की बकाया कोई रकम, जो उसके लेखे में निगम के अंशदान तथा उस पर ब्याज तक हो सकती है, अथवा
- (ख) जहां अभिदाता, उसके अवचार अथवा धोर प्रसाद के कारण नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया हो अथवा अस्थायी सेवा सहित पांच वर्ष की लगातार सेवा से पहले त्याग-पत्र दे दिया हो, तो,
- जमा अंशदान का ब्याज सहित पूरा अथवा कोई भाग।

(ख) विनियम 14 के उप-विनियम (1) के बाद निम्नलिखित नये उप-विनियम (2), (3) और (4) जोड़ दिये जायेंगे :—

“(2) (क)—निगम द्वारा लगाये नियमों तथा शर्तों के अनुसार उप-विनियम (1) के दूसरे परन्तुक के अधीन धन निकालने की मंजूरी दी जा सकती है—

(i) अभिदाता पर वास्तविक रूप से आश्रित, निम्नलिखित मामलों में उसके किसी बच्चे की उच्च शिक्षा, जहां जरूरी हो यात्रा व्यय सहित खर्च के लिए, अर्थात्—

(1) हाई स्कूल स्तर के बाद भारत से बाहर शैक्षणिक, तकनीकी व्यावसायिक अथवा वृत्तिक पाठ्यक्रमों के लिए, और

(2) हाई स्कूल के बाद भारत में किसी अन्य डाक्टरी, इंजीनियरिंग अथवा अन्य तकनीकी अथवा विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए

परन्तु यह कि पाठ्यक्रम तीन वर्ष से कम न हो,

(ii) अभिदाता के पुत्र अथवा पुत्री और यदि उसकी कोई पुत्री न हो तो उस पर आश्रित कन्या के विवाह पर व्यय के लिए,

(iii) अभिदाता अथवा उस पर वास्तविक रूप से आश्रित व्यक्ति की बीमारी, जहां जरूरी हो यात्रा व्यय सहित खर्चों के लिए।

परन्तु यह कि इस प्रकार निकाली गई राशि को अभिदाता स्वेच्छा से पूरी राशि अथवा उसका कुछ भाग निधि में वापिस लौटा देगा।

(ख) खण्ड (ग) से (अ) की शर्तों के अनुसार उप-विनियम (1) के दूसरे परन्तुक के अधीन भी निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए रुपया निकाला जा सकता है, अर्थात्—

- (i) मकान अथवा मकान के लिए स्थान खरीदना;
- (ii) मकान बनाना;
- (iii) ऐसी खरीद अथवा निर्माण के लिए ऋण की अदायगी (इसमें ऋण मकान अथवा जमीन अथवा निर्मित मकान पर सुरक्षित होना चाहिए।)
- (iv) अभिदाता के पास पहले से अथवा उपाजित मकान का पुनर्निर्माण अथवा विस्तार करने के लिए।

(ग) अभिदाता द्वारा खरीदा अथवा निर्मित किया गया मकान, अभिदाता के अपने लिए और स्थान उसके अपने लिए मकान निर्माण हेतु होना चाहिए; मकान अथवा स्थान अभिदाता के कार्य स्थान अथवा उस स्थान पर होना चाहिए, जहां उसने निवृत्ति के बाद रहने का स्थान लिखित रूप में घोषित किया गया हो।

(घ) इस प्रकार निकालने के लिए स्वीकृत राशि वास्तविक उद्देश्य के लिए जरूरी रकम से ज्यादा नहीं होगी, कोई भी ज्यादा ली गई राशि बाद में वापिस कर दी जायेगी।

(ङ) अभिदाता को किसी भी समय, निम्नलिखित मामलों में, जैसा निगम निदेश करे, निगम को आश्वस्त करने के लिए कहा जा सकता है, अर्थात्—

- (i) रकम निकालने के लिए मांगी गई स्वीकृति, जो मिल गई अथवा मांगी गई है, और जिसके लिए निवेदन किया है, उन्हीं वास्तविक उद्देश्यों के लिए है;
- (ii) यह मांगी गई स्वीकृत की रकम अन्य धन सहित अथवा निकालने के लिए स्वीकृति राशि जो मांगी गई अथवा मिल गई उस उद्देश्यों के लिए काफी है;
- (iii) अभिदाता ने मकान अथवा स्थान पर उचित हक प्राप्त कर लिया अथवा कर लेगा; और
- (iv) अभिदाता ने मकान के निर्माण के लिए सभी आवश्यक स्वीकृतियां और अनुमोदन प्राप्त कर लिया अथवा कर लेगा, और अभिदाता इन सभी आवश्यकताओं का पालन करेगा।

(च) जब धन मकान बनाने के लिए लिया जाये, तो अभिदाता को पूरी राशि अथवा कोई भाग लेने के छः मास के भीतर अथवा ऐसे अरसे में जो निगम मंजूर करे, भवन बनना शुरू हो जायेगा; और अठारह मास से पहले अथवा ऐसे अरसे से पहले जो निगम मंजूर करे, भवन पूरा हो जायेगा।

(छ) जहां यह धन ऋण की अदायगी के लिए लिया जाये, तो धन की पूरी राशि अथवा उसका कोई भाग लेने के तीन मास के भीतर अदा हो जाना चाहिए।

(ज) जहां यह धन भवन-निर्माण के लिए लिया जाये, तो राशि किस्तों में जो चार से ज्यादा नहीं होगी, भवन-निर्माण की प्रगति के साथ ऐसे अरसे अथवा अरसों पर जो निगम निश्चित करे, दी जायेगी।

(झ) अभिदाता स्थान अथवा मकान को अपने पूर्ण स्वामित्व में रखेगा और निगम की पूर्व स्वीकृति के बिना उसका परिवर्तन, गिरवी अथवा धरोहर नहीं रखेगा, बोधी पाये जाने पर अभिदाता को सारी राशि एक ही किस्त में लौटानी होगी।

(ञ) इस प्रकार ली गई राशि को अभिदाता स्वेच्छा से पूरा अथवा उसका कुछ भाग निधि को लौटा सकता है।

(3) उप-विनियम (2) के उद्देश्य के लिए “मकान की खरीद” अभिव्यक्ति में सहकारी हाऊसिंग सोसाइटी के सदस्य के नाते, शेयर खरीद कर अथवा सोसाइटी में धन जमा कराकर सोसाइटी से आवासीय स्थान का अर्जन; और (ii) आवासीय मकान अथवा परिसर की किराया खरीद आधार पर खरीद अथवा हाऊसिंग बोर्ड, नगर विकास प्रन्यास अथवा सामयिक कानून के अधीन निर्मित व स्थापित अन्य किसी अधिकरण से उप-विनियम (2) के खण्ड (ग), (घ), (ङ) (i), (ङ) (ii), (झ) और (ञ) के अनुसार अर्जन तथा खरीद शामिल हैं।

(4) जब धन उप-विनियम (2), उप-विनियम (3) के साथ पठित के अधीन मंजूर किया जाये तो निम्नलिखित शर्तें भी लागू होंगी—

(क) अभिदाता को निगम को आश्वस्त करने को कहा जा सकता है कि उसने सहकारी हाऊसिंग सोसाइटी के शेयरों का हक प्राप्त कर लिया है अथवा सोसाइटी में धन जमा करने का प्रमाण अथवा किराया खरीद आधार पर आवासीय मकान अथवा परिसर की प्राप्ति का अधिकार अथवा हाऊसिंग बोर्ड, नगर विकास प्रन्यास अथवा सामयिक कानून के अधीन निर्मित अथवा स्थापित अन्य अधिकरण से खरीद; .

(ख) अभिदाता पूरी राशि अथवा उसका कुछ भाग निकालने के छः मास के भीतर अथवा ऐसे अरसे के भीतर जो निगम मंजूर करे, आवासीय स्थान प्राप्त कर लेगा;

(ग) राशि किस्तों में जो चार से ज्यादा नहीं होगी, ऐसे अरसे अथवा अरसों पर, जो नियम निश्चित करे, दी जायेगी;

(घ) अभिदाता निगम की पूर्व स्वीकृति के बिना ऐसे शेयरों अथवा जमा अथवा इस प्रकार नियतन किये गये आवासीय स्थान पर कोई भार, अथवा परिवर्तन अथवा हस्तांतरण नहीं करेगा, बोधी पाये जाने पर सारी राशि एक ही किस्त में लौटानी पड़ेगी।

#### विनियम 14-क

विनियम 14 के बाद निम्नलिखित (1), (2) और (3) खण्डों वाला विनियम 14-क जोड़ा जायेगा :—

“अभिदाता द्वारा विनियम 14 के उप-विनियम (2) के खण्ड

(क) के अनुसार किसी समय एक अथवा अधिक उद्देश्यों के लिए ली गई रकम, उसके खाते में ब्याज सहित जमा अभिदान अथवा छः मास का वेतन (वेतन विनियम 8 के स्पष्टीकरण में वर्णित) जो भी कम हो, से ज्यादा नहीं होगी। (i) धन निकालने का उद्देश्य

(ii) अभिदाता का स्तर (iii) अभिदाता का अभिदान तथा उस पर ब्याज की ध्यान में रखते हुए, मंजूरी देने वाला अधिकारी इस सीमा से अधिक, अभिदाता का ब्याज सहित जमा के 3/4 भाग तक निकालने की स्वीकृति दे सकता है।

(2) विनियम 14 के उप विनियम (2) के खण्ड (ख) के अधीन (सिवाय उस खण्ड के उपखण्ड (iv) यह राशि अभिदाता के अभिदान तथा उस पर ब्याज से ज्यादा नहीं होगी।

परन्तु यह कि निगम के नियमों के अधीन जो यह अग्रिम लेता है, तो इस उप विनियम के अधीन निकाली गई राशि तथा मकान के लिए लिया गया अग्रिम 1,00,000/- रु० अथवा पांच वर्ष के वेतन, जो भी कम हो, से ज्यादा नहीं होगा।

(3) अभिदाता को विनियम 14 के उपविनियम (2) के अधीन निगम के द्वारा निश्चित श्रम से भीतर, निगम को आश्वस्त करना होगा कि इस प्रकार ली गई राशि, वास्तविक उद्देश्य पर खर्च की गई है, ऐसा कर पाने में असमर्थ होने पर अभिदाता को सारी राशि अथवा वह राशि जो वास्तविक उद्देश्य पर खर्च नहीं की गई, विनियम 9 के अधीन ब्याज सहित वापिस कर दी जायेगी। इस अदायगी के अदान कर सकने पर निगम उसकी उपलब्धियों में से एक दम अथवा निर्धारित किस्तों में काटने का आदेश देगी।

#### विनियम 14-ख

विनियम 14-क के बाद निम्नलिखित नया विनियम 14-ख जोड़ा जायेगा :—

“एक अभिदाता द्वारा विनियम II अथवा II-क में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए अग्रिम लिया धन, निगम की स्वीकृति से, इस प्रकार के अग्रिम को बकाया को विनियम 14 की शर्तों के पूरा करने पर अग्रिम में बदला जा सकता है”

#### विनियम 14-ग

विनियम 14-ख के बाद निम्नलिखित विनियम 14-ग जोड़ा जायेगा :—

“(1) प्रबन्धक कुछ शर्तों के अधीन, जैसा वे उचित समझें, विनियम 4 और विनियम 5 (iii) (ख) के परन्तुक तथा विनियम 5-क के अधिकारों को छोड़कर, निगम के किसी अधिकारी को अपनी ओर से सभी अथवा कुछ अधिकार दे सकते हैं।

(2) उपविनियम (1) के शर्तों पर दुप्रभाव डाले बिना,

(क) विनियम II अथवा उपविनियम II-क के अधीन जब अग्रिम अभिदाता के छः मास के वेतन अथवा अभिदाता का ब्याज सहित अभिदान का आधा, जो भी ज्यादा हो तो अधिकारियों के मामले में सचिव/नियन्त्रक तथा अन्यो के मामले में प्रबन्धक (प्रशासन)/प्रबन्धक (स्थापना तथा लेखा) और कोई भी अन्य अग्रिम महाप्रबन्धक मंजूर कर सकता है;

(ख) विनियम 14 के उपविनियम (1) के पहले परन्तुक के अधीन अग्रिम, अधिकारियों के मामले में सचिव/नियन्त्रक तथा अन्यो के मामले में प्रबन्धक (प्रशासन)/प्रबन्धक (स्थापना तथा लेखा) मंजूर कर सकता है;

(ग) विनियम 14 के उपविनियम (1) के दूसरे परन्तुक के अधीन, अग्रिम जो अभिदाता के छः मास का वेतन अथवा अभिदाता का ब्याज सहित अभिदान का आधा जो भी ज्यादा हो, अधिकारियों के मामले में सचिव/नियन्त्रक तथा अन्यो के मामले में प्रबन्धक (प्रशासन)/प्रबन्धक (स्थापना तथा लेखा) और उस विनियम के अधीन कोई अन्य अग्रिम महाप्रबन्धक मंजूर कर सकता है।

#### विनियम 15—

(क) इस विनियम में जहां भी “उपविनियम” तथा “नियम” शब्द आये हैं, वे “उपविनियम” तथा “विनियम” से प्रतिस्थापित होंगे।

(ख) विनियम 15(1) के दूसरे परन्तुक के रूप में निम्नलिखित जोड़ दिया जायेगा :—

“परन्तुक आगे यह कि जब अभिदाता इस निधि में अभिदान करने से पहले किसी निधि में अभिदान कर रहा था और वह जमा उसके इस निधि खाते में परिवर्तित हो गई है, तो जब तक अभिदाता इन विनियमों के अनुसार नामांकन न दे तो पहले का दिया हुआ नामांकन इन विनियमों के अधीन दिया हुआ नामांकन ही माना जाता रहेगा।”

(ग) उपविनियम (v) के खण्ड (क) का मसौदा निम्नलिखित प्रकार से परिवर्तित होगा :—

“(क) विशिष्ट नाते के सम्बन्ध में जिसकी मृत्यु अभिदाता से पहले हो जाती है, उसका नाति-अधिकार ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को परिवर्तित हो जायेगा, जैसा नामांकन में उल्लिखित हो, परन्तुक यह कि यदि अभिदाता का परिवार है, तो वह व्यक्ति परिवार के सदस्य/सदस्यों में से होगा, जहां इस खण्ड के अधीन अभिदाता एक से अधिक व्यक्ति को अधिकृत करे तो वह प्रत्येक नागरिक को देय राशि का भाग, इस प्रकार निविष्ट कर देगा, जिसमें नामित को देय सारी राशि शामिल हो।”

(घ) उपविनियम (V) (ख) के दूसरे परन्तुक के रूप में निम्नलिखित जोड़ा जायेगा :—

“परन्तुक आगे यह कि यदि अभिदाता के परिवार में नामांकन के समय एक ही सदस्य है, तो वह नामांकन में व्यवस्था कर देगा कि तदनुसार खण्ड (क) के अधीन उसके परिवार में सदस्य/सदस्यों के होने से वह नामांकन अविधिमान्य हो जायेगा।

(ङ) उपविनियम (vi) के प्रारम्भ में आय शब्द “तत्काल”, “तत्काल ही” शब्दों से प्रतिस्थापित होगा उसी उपविनियम की छठी पंक्ति में आया “परन्तु” शब्द “परन्तुको” हो जायेगा।

(च) विनियम 16 के स्पष्टीकरण में “स्पष्टीकरण” के बाद (i) संख्या जोड़ दी जायेगी और इसी स्पष्टीकरण (i) में निम्नलिखित तीसरा परन्तुक भी जोड़ दिया जायेगा :—

“परन्तुक आगे यह कि ऐसे मामलों में जहां अभिदाता के वैयक्तिक कानून अनुसार अंगीकरण स्वीकार्य हो, तो अंगीकृत बालक उसका अपना बालक माना जायेगा।”

(छ) विनियम 15 में निम्नलिखित सपष्टीकरण, स्पष्टीकरण II के रूप में जोड़ा जायेगा :—

“स्पष्टीकरण II—इस विनियम के लिए “व्यक्ति” में केन्द्रीय सरकार, प्रान्तीय सरकार, स्थानीय अधिकारी कम्पनी अथवा समिति अथवा व्यक्तियों का समूह, निगमित अथवा अनिगमित अथवा कोई अधिकार से अभिहित व्यक्ति, शामिल हैं।”

**विनियम 15-क :**

विनियम 15 के बाद निम्नलिखित विनियम 15-क जोड़ा जायेगा :—

“विनियम 15 पर विपरीत प्रभाव डाले बिना, अभिदाता किसी को नामित कर सकता है, जो भविष्य निधि अधिनियम, 1925 की परिभाषा के अनुसार आश्रित है। यदि निगम आश्रित है कि इन विनियमों के परिशिष्ट में दिये प्रपत्र (आई०एफ० सी० पी० एफ-7) में भरा जाये।”

**विनियम 16—**

(क) विनियम 16 के उपविनियम ‘I’ के खण्ड (ख) क बाद निम्नलिखित तीसरा परन्तुक जोड़ा जायेगा :—

“परन्तुक आगे यह कि यदि नामांकन आश्रित अथवा आश्रितों के पक्ष में कायम है, तो अभिदाता के लेख में जमा रकम अथवा नामांकन में उल्लिखित कुछ भाग, इस उपखण्ड पर विपरीत प्रभाव डाले बिना, नामांकन में उल्लिखित अनुपात में नामित अथवा नामितों को देय हो जायेगी।”

(ख) विनियम 16 का खण्ड 2(ii) निम्नलिखित खण्ड से प्रतिस्थापित होगा :—

“(ii) जब अभिदाता कोई परिवार नहीं छोड़ता :—

(क) यदि अभिदाता इन विनियमों के अधीन किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के नाम नामांकन करता है, तो जो उस पर आश्रित है अथवा है, जो भविष्य निधि अधिनियम, 1925 की धारा (2) के खण्ड (ग) की परिभाषा अनुसार कायम है, तो निधि ने उसका जमा अथवा कुछ भाग, जैसा भी मामला हो, नामांकन में वर्णित अनुपात के अनुसार नामित अथवा नामितों को देय हो जायेगा;

(ख) यदि भविष्य निधि अधिनियम 1925, की धारा (2) के खण्ड (ग) की परिभाषा अनुसार, नामांकन ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में कायम है, जो आश्रित नहीं है, तो निधि में उसका जमा अथवा जैसा भी मामला हो, उसका कुछ भाग जो नामांकन में वर्णित है,

यदि यह राशि पांच हजार से ज्यादा नहीं है, तो ऐसे नामित को देय हो जायेगी।

(ग) यदि नामांकन कायम नहीं है अथवा नामांकन में निधि में जमा कुछ भाग का उल्लेख है अथवा जैसा भी मामला हो और वह भाग जिसका उल्लेख नामांकन में नहीं है, तो वह राशि अथवा उसका कुछ भाग, जैसा भी मामला हो, यदि राशि पांच हजार से ऊपर न हो, तो ऐसे व्यक्ति को देय होगी, जो प्रबन्धकों को उसका हकदार लगेगा।

(घ) उप-खण्ड (क) अथवा (ख) अथवा (ग), के अधीन कुछ राशि अथवा उसका कुछ भाग जो किसी को भी देय नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को जो भविष्य निधि अधिनियम, 1925, की धारा 4 के खण्ड (ग) के अनुसार, वसीयतनामा अथवा मृतक की सम्पत्ति मिलने के अधिकार का प्रमाणपत्र अथवा उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा, को देय हो जायेगी।

**टिप्पणी :—**भविष्य निधि अधिनियम, 1925 की धारा 2 के खण्ड (ग) की परिभाषा अनुसार जब नामित अथवा अन्य व्यक्ति अभिदाता का आश्रित है, तो उस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन नामित अथवा अन्य व्यक्ति को देय राशि का अधिकार इन विनियमों के अनुसार आश्रित में निहित होगा। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम कर्मचारी भविष्य निधि विनियमों अन्तर्गत निम्नलिखित एक नया प्रपत्र संख्या आई० एफ० सी० पी० एफ० 7 जोड़ा जायेगा :—

#### नामांकन प्रपत्र

(जब अभिदाता का परिवार है, परन्तु वह विनियम 15 की शर्तों के अधीन एक आश्रित को नामित करने का इच्छुक है) सेवा में,

श्रीमन् प्रबन्धक,  
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम  
कर्मचारी भविष्य निधि।

महोदय,

मैं भारतीय औद्योगिक वित्त निगम कर्मचारी भविष्य निधि विनियम 15-क की शर्तों के अनुसार निम्नलिखित आश्रितों को, अपनी मृत्यु की दशा में, जो राशि मेरे निधि खाते में जमा होगी और देय हो गई है अथवा हो जायेगी, परन्तु अदा नहीं हुई, को प्रत्येक के नाम के सामने उल्लिखित अनुसार अदा करने का निदेश करता हूँ।

| नामित अथवा नामितों का नाम और पता | अभिदाता से सम्बन्ध | नामित अथवा नामितों की आयु | *प्रत्येक को कुल में से देय राशि | परिवार होते हुए भी आश्रित को नामित करने के कारण | किसी ऐसे व्यक्ति का नाम, पता और सम्बन्ध जिसके अभिदाता द्वारा नामित के पूर्व देहान्त से अधिकार परिवर्तित हो जायेगा |
|----------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|
|----------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|

स्थान—

दिनांक

सन्

दो साक्षियों के हस्ताक्षर

अभिदाता के हस्ताक्षर

1. नाम—

पता—

2. नाम—

पता—

मैंने अभिदाता के हस्ताक्षर सत्यापित किये  
प्रबन्धक

धरमदास खन्ना

## STATE BANK OF INDIA

## Central Office

## NOTICE

Bombay, the 9th May 1970

In terms of Section 29(1) of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, the State Bank of India, after consulting the Board of Directors of the State Bank of Saurashtra and with the approval of the Reserve Bank of India, have appointed Shri B. K. Chatterji as the General Manager of the State Bank of Saurashtra, with effect from the 3rd May, 1970 to 2nd May, 1973 (both days inclusive).

Sd. ILLEGIBLE  
Managing Director

## THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi-1, the 28th April 1970

No. 8-CA(1)/5/70-71—In pursuance of Clause (iii) of Regulation 10(1) of the Chartered Accountants Regulations, 1964, it is hereby notified that the Certificate of practice issued to the following members shall stand cancelled for the period mentioned against their names, as they do not desire to hold their certificate of practice :—

| Sl. No. | Member-ship No. | Name and address.  | Period during which the certificates shall stand cancelled. |
|---------|-----------------|--|---|
| 1.      | 10544           | Shri Divakar Sharma, A.C.A.,<br>Mohinder Nagar,<br>Canal, JAMMU (J. & K. State).               | 15-3-1970<br>to<br>30-6-1970                                |
| 2.      | 10785           | Shri Aspi Jal Jussawalla, A.C.A.,<br>R-13, Cusrow Baug,<br>Colaba Causeway,<br>Fort, BOMBAY-1. | 2-3-1970<br>to<br>30-6-1970                                 |

New Delhi, the 2nd May 1970

No. 8-CA(1)/6/70-71.—In pursuance of clause (iii) of Regulation 10(1) of the Chartered Accountants Regulations, 1964, it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to Shri Rabindra Nath Bhar, A.C.A., of Daspara Lane, P.O. Chinsura, Distt. Hooghly (West Bengal), (Membership No. 7104), shall stand cancelled for the period from 30th April, 1970 to 30th June, 1970, as he does not desire to hold the Certificate of Practice.

The 4th May 1970

No. 5-CA(1)/4/70-71.—With reference to this Institute's Notification No. 4-CA(1)/13/69-70, dated the 3rd October, 1969, it is hereby notified in pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1964, that in exercise of the powers conferred by Regulation 17 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members, with effect from the 23rd April, 1970, the name of Shri Krishan Swarup Saxena, A.C.A., Jayam Industries Premises, Station Road, Faridabad City, (Membership No. 6934).

C. BALAKRISHNAN  
Secretary

Calcutta-16, the 7th May 1970

(COST ACCOUNTANTS)

No. 39-CWA(32)/70.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 39 of the Cost and Works Accountants Act 1959, (Act No. 23 of 1959), the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has made the following amendments in the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, the same having been previously published and approved by the Central Government as required by sub-section (3) of the said Section.

In the said Regulations :

I. For the existing sub-regulations (3) and (4) of Regulation 7, the following shall be substituted :

"(3) An associate shall pay an annual membership fee of Rs. 50 which shall be due and payable on the 1st April in each year :

Provided that only half the amount of the annual membership fee shall be payable for the first year by a person admitted on or after 1st October in any year.

(4) A fellow shall pay an annual membership fee of Rs. 100 which shall be due and payable on the 1st April in each year :

Provided that an associate who is admitted as a fellow during a year may pay Rs. 50 or Rs. 25 only as membership fee for that year according as he is admitted as a fellow prior to the 1st October, or after the 1st October, of the year."

II. Sub-regulations (6) and (7) of Regulation 7 shall be deleted.

III. After Regulation 25 and before Regulation 26, the following new Regulation 25A shall be inserted :—

"25A. *Registration de novo*.—A person whose registration has been cancelled under Regulation 25 may apply in Form I to become a registered student *de novo* and on his application being granted, he shall be deemed for all purposes to have been admitted as a fresh registered student except that he shall be entitled to the exemption from individual subjects/groups of the Intermediate or Final Examination, as the case may be, previously secured by him under his former registration."

IV. In Regulation 32A, the following shall be added at the end as sub-regulation (7) :—

"(7) A candidate who is admitted as a registered student under Regulation 25A shall be entitled to exemption from the subjects of the Intermediate Examination corresponding to the subjects in which he had passed or obtained exemption under his former registration prior to its cancellation under Regulation 25."

V. In Regulation 35A, the following shall be added at the end as sub-regulation (5) :—

"(5) A candidate who is admitted as a registered student under Regulation 25A shall be entitled to exemption from the subjects of the Final Examination corresponding to the subjects in which he had passed or obtained exemption under his former registration prior to its cancellation under Regulation 25."

VI. For the existing Regulation 51, the following shall be substituted :

"51. *Examination Certificate and Qualifying Letters*.—Every candidate passing the examination under

this Chapter shall be furnished with a certificate to that effect in Form 'J' and shall be entitled to use the letters "DIP, MA" after his name to indicate that he has passed the Management Accountancy Examination of the Institute."

VII. In Regulation 120, after the existing sub-regulation (4), the following sub-regulation (5) shall be added :—

"(5) Notwithstanding anything contained in these Regulations, an elected or co-opted member of a Regional Council shall be deemed to have vacated his seat if he is declared by the Regional Council to have been absent without sufficient excuse from three consecutive meetings of the Regional Council, or if his name is, for any reason, removed from the Regional Register of Members under the provisions of these Regulations, and the vacancy so caused may be filled by co-option of another member by the Regional Council concerned. A member so co-opted shall hold office till the expiry of the duration of the said Regional Council.

S. N. GHOSE  
*Secretary*

# INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA

(INCORPORATED UNDER THE INDUSTRIAL FINANCE

CORPORATION ACT, 1948 (XV OF 1948)

*Amendments to I.F.C. Employees' Provident Fund Regulations*

*New Delhi, the 11th May 1970*

No. 2/70.—In exercise of the power conferred by Section 43(1) of the Industrial Finance Corporation Act, 1948 (XV of 1948), the Board after consultation with the Industrial Development Bank of India and with the previous sanction of the Central Government have made the following amendments to the Industrial Finance Corporation of India Employees' Provident Fund Regulations :—

## Regulation 2 :

The words "and supervisory staff" shall be added after the word "Officers" in line 4 and the word "and" appearing in the same line after the word "Officers" shall be deleted and substituted by the punctuation mark ",". The words "and one of the subordinate staff" shall also be added after the words "one of the clerical staff"

## Regulation 5 : Sub-clause (i)—

The words "in superior service and every permanent employee in subordinate service who is in receipt of a pay of Rs. 30/- or more per mensem" shall be deleted. Further, the second sentence of the Regulation reading "An employee in subordinate service who is in receipt of a pay or less than Rs. 30/- per mensem may subscribe to the Fund if he desires to do so" shall also be omitted in full.

## Sub-clause (iii)—

For the existing sub-clause (iii), the following sub-clauses shall be substituted :

- (a) A temporary employee other than an employee who is already subscribing to some other provident fund, may subscribe to the Fund, if so permitted by the Administrators.
- (b) Any other person in receipt of other than casual remuneration from the Corporation may also subscribe to the Fund, if so permitted by the Administrators ;

Provided that where any sum is standing to the credit of such person in the Fund and has become payable to him by reasons of the provisions of Regulation 14, such sum may, in exceptional cases, if so permitted by the Administrators, continue to stand to his credit in the Fund for such time as he is in receipt of other than casual remuneration from the Corporation, and interest shall, notwithstanding anything contained in Regulation 13, accrue on such sum.

## Regulation 5-A :

A new Regulation 5-A shall be added after Regulation 5 reading as under :—

"Any employee required or permitted under Regulation 5 to subscribe to the Fund, if permitted by the Administrators to do so, pay to his credit in the Fund any amount granted to him by his former employer or employers by way, or in lieu of retirement benefits in respect of his service under such employer or employers.

Provided that the Corporation shall not be required to make any contribution in respect of any amount so paid into the Fund."

## Regulation 6 :

The words "eight annas" appearing in the sixth line of the Regulation shall be substituted by the words "half rupee".

## Regulation 8 :

The explanation to this Regulation shall be redrafted to read as under :—

"Explanation : For purposes of this Regulation and Regulation 6, "pay" shall mean the amount drawn by an employee as—

- (i) pay which has been sanctioned for a post held by him substantively or in officiating capacity, or to which he is entitled by reasons of his position in a cadre;
- (ii) overseas pay, special pay and personal pay;
- (iii) any other emoluments which may be specially classed as pay by the Board."

## Regulation 9 :

The words "one anna" appearing in the eighth line shall be substituted by the word "paise".

## Regulation 11 :

(A) For the existing clauses (i), (ii) and (iii) of sub-regulation 1(a), the following clauses shall be substituted :—

- "(i) to pay expenses in connection with the illness, confinement or disability, including where necessary, the travelling expenses, of the subscriber or any person actually dependent on him;
- (ii) to meet the cost of higher education including where necessary the travelling expenses of the subscriber or any person actually dependent on him in the following cases, namely—
  - (a) for education outside India for an academic, technical, professional or vocational course beyond the High School stage; and
  - (b) for any medical, engineering or other technical or specialised course in India beyond the High School stage, provided that the course of study is for not less than three years;



- (iii) to pay obligatory expenses on a scale appropriate to the status which by customary usage the subscriber has to incur in connection with marriages or other ceremonies of himself or of his children or of any other person actually dependent on him :

Provided that the condition of actual dependence shall not apply in the case of a son or daughter of the subscriber or in the case of an advance required to meet the funeral expenses of the parent of a subscriber;

- (iv) to meet the cost of legal proceedings instituted by the subscriber for vindicating his position in regard to any allegation made against him in respect of any act done or purporting to be done by him in the discharge of his official duty, advance in this case being available in addition to any advance admissible for the same purpose from any other Corporation source :

Provided that the advance under this sub-clause shall not be admissible to a subscriber who institutes legal proceedings in any court of law either in respect of any matter unconnected with his official duty or against the Corporation in respect of any condition of service or penalty imposed on him;

- (v) to meet the cost of his defence where the subscriber is prosecuted by the Corporation in any court of law;
- (vi) to meet any other expenses or liability which, in the opinion of the Corporation is unforeseen and extraordinary and beyond the ordinary means of the subscriber."

(B) Clause (ii) of sub-regulation 1(b) of Regulation 11 shall be substituted by the following clause :—

"be granted until the final repayment of the previous advance."

(C) The following proviso shall be added after the figure "24" at the end of the first sentence of sub-regulation 2(a) of Regulation 11 :—

"Provided that in special cases where the amount of advance exceeds 3 months' pay of the subscriber as provided by clause (b) of sub-regulation (1), the Corporation may fix such number of instalments to be more than 24 but in no case more than 36."

#### Regulation 11-A :

A new Regulation numbered 11-A and containing clauses (1), (2) and (3) shall be added after Regulation 11, reading as under :—

- "(1) At the discretion of the Corporation and subject to such conditions and limitations as it may impose an advance may be granted to a subscriber on application, from the amount standing to his credit in the Fund, for the purpose of purchasing shares in a Co-operative Housing Society or of making any deposit or payment of money by way of earnest or otherwise, in each case solely with a view to securing a suitable house or premises for his residence or the residence of any person dependent on him.
- (2) An advance under this Regulation shall be permitted only once during the service of the employee and shall not exceed the amount of the subscriber's subscriptions to the Fund and interest thereon, or the amount actually required for the purpose for which the advance has been applied for, whichever is less.

- (3) An advance under this Regulation shall be recovered in such number of monthly instalments, at such times and of such amount, as the Corporation may direct, the number of instalments not exceeding 120 in any case. A subscriber may at his option repay more than one instalment in one month and each instalment shall be a number of whole rupees."

#### Regulation 12 :

(A) The existing Regulation shall be numbered as sub-regulation (1) and a new sub-regulation numbered (2) shall be added after sub-regulation (1) of Regulation 12, reading as under :—

"(2) Where sums are withheld from subscriptions to the Fund or withdrawn from the amount subscribed thereto by the subscriber under sub-regulation (1)(b), the policy of insurance in respect of which such sums are withheld or withdrawn shall be transferred to the Corporation in consideration of the payment of premium on such policy and on such terms and conditions as the Corporation may impose in respect of the amount, if any, recovered by the Corporation from the insurer".

#### Regulation 13 :

The existing Regulation shall be substituted as under :—

"Interest on all sums standing in the books of the Fund to the credit of a subscriber shall be payable upto the end of the month preceding that in which payment is made or upto the end of the sixth month after the month in which such amount became payable, whichever of these periods be less.

Provided that no interest shall be paid in respect of any period after the date which the Corporation intimates to the subscriber or his nominee as the date on which the Corporation is prepared to make payment of the amount standing to the credit of the subscriber".

#### Regulation 14 :

(A) The existing Regulation shall be numbered as sub-regulation (1) and the sub-regulation (1) as so re-numbered shall be replaced by the following sub-regulation :—

- (1) The sum standing to the credit of a subscriber shall become payable on the termination of his service or on his death.

"Provided that a subscriber on leave preparatory to retirement may at his option withdraw from the sums standing to his credit in the Fund an amount not exceeding his own subscriptions and the interest thereon :

Provided also that a subscriber, including any person permitted to subscribe to the Fund under Clause (iii) of Regulation 5, may at any time after the completion of 20 years of service or during the 10 years immediately preceding the date of his retirement or the date of expiry of his specified tenure of office, be permitted by the Corporation at its discretion, to withdraw, for the purposes and subject to the provisions, contained in sub-regulations (2), (3) and (4), from the sums standing to his credit in the Fund such amount as is specified in Regulation 14-A".

Provided further, that there may, if the Board so directs in the case of Officers, and Chairman in the case of others, be deducted therefrom and paid to the Corporation :—

- (a) any amount due under a liability incurred by the subscriber to the Corporation upto the total amount contributed by the Corporation to his account, including the interest credited in respect thereof; or
- (b) where the subscriber has been dismissed from his employment on account of misconduct or gross negligence or where the subscriber has resigned his employment under the Corporation within five years of the commencement of his *continuous service including temporary service*, the whole or any part of the amount of such contributions together with the interest credited in respect thereof.

(B) New sub-regulations (2), (3) and (4) shall be added after sub-regulation (1) of Regulation 14 reading as under :—

“(2)(a)—Subject to such terms and conditions as may be imposed by the Corporation, a withdrawal under the second proviso to sub-regulation (1) may be permitted for—

- (i) meeting the cost of higher education, including where necessary, the travelling expenses, of any child of the subscriber actually dependent on him in the following cases, namely—
  - (1) for education outside India for academic, technical, professional or vocational course, beyond the High School stage; and
  - (2) for any medical, engineering or other technical or specialised course in India beyond the High School stage, provided that the course of study is for not less than three years;
- (ii) meeting the expenditure in connection with the marriage of the subscriber's son or daughter and if he has no daughter, of any other female relation dependent on him;
- (iii) meeting the expenses in connection with the illness, including where necessary, the travelling expenses, of the subscriber or any person actually dependent on him.

Provided that a subscriber may, at his option, return to the Fund in lump sum the whole or any part of the sum so withdrawn by him.

(b) Subject to provisions of clauses (c) to (j), a withdrawal under the second proviso to sub-regulation (1) may also be permitted for the following purposes, namely—

- (i) purchase of a house or a site for a house;
- (ii) building a house;
- (iii) repayment of a loan taken for such purchase or building (including such a loan secured on the house or site purchased or house built);
- (iv) reconstructing or making additions or alterations to a house already-owned or acquired by the subscriber.

(c) The house purchased or built should be for the subscriber himself and in the case of a site, it should be for building a house for the subscriber himself; the house or site shall be at the station where the subscriber is working or at the place, to be declared by him in writing, as the place where he intends to reside after retirement.

(d) The amount permitted to be withdrawn shall not exceed the amount required for the purpose for which withdrawal is permitted; any excess of the amount actually required shall forthwith be refunded.

(e) The subscriber may at any time be required to satisfy the Corporation, in such manner as it may specify of any one of the following matters, namely—

- (i) that the amount sought to be withdrawn or permitted to be withdrawn is actually required for the purpose for which withdrawal is sought or has been permitted, and that it has been applied to such purpose;
- (ii) that the amount sought to be withdrawn or permitted to be withdrawn, together with other funds, if any, available to the subscriber, is sufficient for the purpose for which withdrawal is sought or has been permitted;
- (iii) that the subscriber has obtained or will obtain a good title to the site or the house; and
- (iv) that the subscriber has obtained or will obtain all the permissions and approvals necessary for building the house;

and the subscriber shall comply with such requirements.

(f) Where the withdrawal is for building a house, such building shall commence before the expiry of six months or such longer period, as the Corporation may allow, and be completed before the expiry of eighteen months, or such longer period as the Corporation may allow, from the date of the subscriber receiving the amount withdrawn or any part thereof.

(g) Where the withdrawal is for repayment of a loan, such repayment should be made within three months from the date of the subscriber receiving the amount withdrawn or any part thereof.

(h) Where the withdrawal is for the purpose of building a house, the amount permitted to be withdrawn may be paid out in such number of instalments, not exceeding four, and at such time or times as the Corporation may determine, having regard to the progress made in the building;

(i) The subscriber shall keep the site or house in his sole ownership and shall not, without the previous written permission of the Corporation, transfer, mortgage or charge the same; in default, the subscriber shall be liable to refund in one instalment the entire amount withdrawn.

(j) A subscriber may, at his option, return to the Fund the whole or any part of the sum withdrawn by him.

(3) For the purpose of sub-regulation (2) the expression “Purchase of a house” shall include the acquisition, as a member of a Cooperative Housing Society, whether by purchase of shares in, or by depositing sums with, such Society, of residential accommodation allotted by the Society; and (ii) the purchase of a residential house or premises on hire purchase basis or otherwise from a Housing Board, City Improvement Trust, or other like authority formed or established under any law for the time being in force and clauses (c), (d), (e)(i), (e)(ii), (i) and (j) of sub-regulation (2) shall, so far as may apply accordingly to advances for such acquisition or purchase.

(4) Where a withdrawal has been permitted under sub-regulation (2), read with sub-regulation (3), the following conditions shall also apply—

- (a) The subscriber may be required to satisfy the Corporation that he has obtained title to the shares in the Co-operative Housing Society concerned or has obtained the documents evidencing the deposit or sums with such Society

or that he has obtained the documents evidencing the right to the residential house or premises purchased on hire purchase basis or otherwise from a Housing Board, City Improvement Trust or other like authority formed or established under any law for the time being in force;

- (b) The residential accommodation is obtained by the member before the expiry of six months, or such longer period as the Corporation may allow, from the date of the subscriber receiving the amount withdrawn or any part thereof;
- (c) The amount may be permitted to be withdrawn in such number of instalments, not exceeding four, and at such time or times as the Corporation may determine;
- (d) Except with the previous written permission of the Corporation the subscriber shall not transfer, assign or create any encumbrance on such shares or such deposit or his interest in the residential accommodation allotted to him, in default the subscriber shall be liable to refund forthwith in one instalment the entire amount withdrawn.

#### Regulation 14-A :

A new Regulation numbered 14-A and containing Clauses (1), (2) and (3) shall be added after Regulation 14, reading as under :—

“(1) Any sum withdrawn by a subscriber at any one time for one or more of the purposes specified in clause (a) of sub-regulation (2) of Regulation 14 or sub-clause (iv) of clause (b) of that sub-regulation from the amount standing to his credit in the Fund shall not ordinarily exceed one-half of his own subscriptions and the interest thereon or six months' pay (pay as defined in Explanation to Regulation 8), whichever is less. The sanctioning authority may, however, sanction the withdrawal of an amount in excess of this limit upto 3/4ths of his own subscriptions and the interest thereon in the Fund having due regard to (i) the objects for which the withdrawal is being made (ii) the status of the subscriber and (iii) the amount of his own subscriptions and the interest thereon in the Fund.

(2) Any sum withdrawn by a subscriber under clause (b) of sub-regulation (2) of Regulation 14 [except sub-clause (iv) of that clause] shall not exceed his own subscriptions and interest thereon.

Provided that in the case of a subscriber who has availed himself of an advance under the rules of the Corporation for the grant of advances for house-building purposes, the sum withdrawn under this sub-regulation together with the amount of advance taken under the rules for the grant of advances for house-building purposes shall not exceed Rs. 1,00,000/- or five years' pay, whichever is less.

(3) A subscriber who has been permitted to withdraw money from the Fund under sub-regulation (2) of Regulation 14 shall satisfy the Corporation within a reasonable period as may be specified by the Corporation that the money has been utilised for the purpose for which it was withdrawn, and if he fails to do so, the whole of the sum so withdrawn or so much thereof as has not been applied for the purpose for which it was withdrawn shall forthwith be repaid in one lump sum, together with interest thereon at the rate determined under Regulation 9, by the subscriber to the Fund, and in default of such payment, it shall be ordered by the Corporation to be recovered from his emoluments either in a lump sum or in such number of monthly instalments, as may be determined by the Corporation”.

#### Regulation 14-B :

A new Regulation numbered 14-B shall be added after Regulation 14-A, reading as under :

“A subscriber who has been granted an advance under Regulation 11 or Regulation 11-A for any of the purposes specified therein, may be permitted by the Corporation to convert the balance outstanding against such advance into a withdrawal under Regulation 14 on his satisfying the relative conditions laid down in that Regulation.”

#### Regulation 14-C :

A new Regulation numbered 14-C shall be added after Regulation 14-B, reading as under :—

“(1) The Administrators may, subject to such conditions as they may think fit to impose, delegate to any Officer of the Corporation as they may specify in this behalf all or any of the powers conferred upon them by these Regulations with the exception of the powers conferred by Regulation 4 and the proviso to Regulation 5(iii)(h) and Regulation 5-A.

(2) Without prejudice to the provisions of sub-regulation (1).

(a) an advance under Regulation 11, or advance under Regulation 11-A upto six months' pay of the subscriber or one half of the subscriber's own subscriptions and interest thereon, whichever is higher, may be sanctioned, by the Secretary/Comptroller in the case of Officers and Manager (Admn.)/Manager (Estt. & Accounts) in the case of others, and any other advance from the Fund may be sanctioned by the General Manager;

(b) Withdrawals under the first proviso to sub-regulation (1) of Regulation 14 may be sanctioned, by the Secretary/Comptroller in the case of Officers and Manager (Admn.)/Manager (Estt. & Accounts) in the case of others;

(c) Withdrawals under the second proviso to sub-regulation (1) of Regulation 14 upto six months' pay of the subscriber or one half of the subscriber's own subscriptions and interest thereon whichever is higher, may be sanctioned by the Secretary/Comptroller in the case of Officers and Manager (Admn.)/Manager (Estt. & Accounts) in the case of others, and any other withdrawal under that Regulation may be sanctioned by the General Manager.

#### Regulation 15 :

(A) The words “sub-rule” and “Rule” wherever they occur in this Regulation shall be substituted by the words “sub-regulation” and “Regulation”.

(B) The following shall be added as second proviso to Regulation 15(j) :—

“Provided further that the nomination made by the subscriber in respect of any other Provident Fund to which he was subscribing before joining the Fund, shall, if the amount to his credit in such other fund has been transferred to his credit in this fund, be deemed to be a nomination duly made under this Regulation until he makes a nomination in accordance with this Regulation.”

(C) Clause (a) of sub-regulation (v) shall be redrafted to read as under :—

“(a) in respect of any specified nominee that in the event of his predeceasing the subscriber, the right conferred upon that nominee shall pass to such other person or persons as may be specified in the nomination provided that such other person or persons shall, if the

subscriber has other members of his family, be such other member or members. Where the subscriber confers such a right on more than one person under this clause, he shall specify the amount or share payable to each of such persons in such a manner as to cover the whole of the amount payable to the nominee."

(D) The following shall be added as second proviso to sub-regulation (v)(b) :—

"Provided further that if at the time of making the nomination the subscriber has only one member of the family, he shall provide in the nomination that the right conferred upon the alternate nominee under clause (a) shall become invalid in the event of his subsequently acquiring other member or members in his family.

(E) The word "Immediate" occurring at the beginning of sub-regulation (vi) shall be substituted by the word "Immediately" and the word "proviso" occurring in the fifth line of the same sub-regulation shall be read as "provisos".

(F) Number (1) shall be added after the word "Explanation" in the Explanation to Regulation 15 and the following proviso shall be added as third proviso to the said Explanation (1) :—

"Provided further that in cases where adoption is recognised by the personal law governing the subscriber, an adopted child shall be considered as a child".

(G) The following explanation shall be added as Explanation II to Regulation 15 :—

"Explanation II : For the purpose of this Regulation "person" includes the Central Government, a State Government, a local authority, a company or association or body of individuals, whether incorporated or not, or any person designated by virtue of office."

*Regulation 15-A :*

A new Regulation numbered 15-A shall be added after Regulation 15, reading as under :—

"Notwithstanding anything contained in Regulation 15, a subscriber may nominate any person, who is a dependant as defined in the Provident Funds Act, 1925, if the Corporation is satisfied that the making or subsistence of a nomination in accordance with that Regulation would cause undue hardship or would not be just and equitable. Such nomination shall be made in the Form (I.F.C.P.F. 7) annexed to these Regulations."

*Regulation 16 :*

A. The following proviso shall be added as third proviso at the end of clause (b) of sub-regulation (i) of Regulation 16 :—

"Provided further that if a nomination under Regulation 15-A in favour of a dependant or dependants subsists, the amount standing to the credit of the subscriber or the part thereof to which the nomination relates shall, notwithstanding anything contained in this sub-clause become payable to the nominee or nominees in the proportion specified in the nomination."

B. Clause (ii) of Regulation 16 shall be substituted by the following clause :—

"(ii) When the subscriber leaves no family :—

(a) if a nomination made by the subscriber in accordance with these Regulations, in favour of any person or persons, who is or are dependant or dependants of the subscriber, as defined in clause (c) of Section 2 of the Provident Funds Act, 1925, subsists, the amount standing to his credit in the Fund or, as the case may be, the part thereof to which the nomination relates, shall become payable to his nominee or nominees in the proportion specified in the nomination;

(b) if any nomination subsists in favour of any person who is not a dependant as defined in clause (c) of Section 2 of the Provident Funds Act, 1925, the amount standing to his credit in the Fund, or as the case may be, the part thereof to which the nomination relates, shall become payable to such nominee if the amount does not exceed five thousand rupees;

(c) if no such nomination subsists or if such nomination relates only to a part of the amount standing to the credit of the subscriber in the Fund the whole or, as the case may be, the part thereof to which the nomination does not relate, shall become payable to any person appearing to the Administrators to be otherwise entitled to receive it, if the whole sum or as the case may be, the part thereof does not exceed five thousand rupees;

(d) any sum or any part thereof which is not payable to any person under sub-clause (a) or sub-clause (b) or sub-clause (c), shall become payable to any person or production of probate, or letters of administration evidencing the grant to him of administration to the estate of the deceased or a succession certificate in accordance with clause (c) of Section 4 of the Provident Funds Act, 1925.

NOTE : When a nominee or other person is a dependant of the subscriber, as defined in clause (c) of Section 2 of the Provident Funds Act, 1925, the amount payable to such nominee or other person under these Regulations vests in the dependant under sub-section (2) of Section 3 of the said Act.

A new form numbered I.F.C.P.F. 7 shall be added at the end of IFC Employees' Provident Fund Regulations as under :—

#### FORM OF NOMINATION

V. (When the subscriber has a family but wishes to nominate a dependant in terms of Regulation 15-A)

To

The Administrators of the Industrial Finance Corporation of India Employees' Provident Fund,

Gentlemen,

In terms of Regulation 15-A of the Industrial Finance Corporation of India Employees' Provident Fund Regulations, I hereby nominate the dependants mentioned below to receive the amount that may stand to my credit in the Fund, in the event of my death

before that amount has become payable, or having become payable has not been paid, and direct that the

said amount shall be distributed among the said persons in the manner shown below against their names :

| Name and address of the nominee or nominees | Relationship with the subscriber | Age of the nominee or nominees | *Amount of share of accumulations to be paid to each | Reasons for nominating dependant when the subscriber has a family | Name, address and relationship of the person, if any, to whom the right of the nominee shall pass in the event of his predeceasing the subscriber |
|---|----------------------------------|--------------------------------|--|---|---|
|---|----------------------------------|--------------------------------|--|---|---|

Dated this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_ at \_\_\_\_\_

Two witnesses to signature.

1. Name \_\_\_\_\_

Address \_\_\_\_\_

2. Name \_\_\_\_\_

Address \_\_\_\_\_

*Signature of subscriber*

*Subscriber's signature verified by me.*

*Manager*

\*NOTE : This column should be filled in so as to cover the whole amount that may stand to the credit of the subscriber in the Fund at any time.

C. D. KHANNA

*General Manager*

#### EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

*New Delhi, the 5th May 1970*

No. 2-12(1)/68-Estt. III.—In pursuance of section 25 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) read with regulation 10 of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 the Chairman, Employees' State Insurance Corporation in consultation with the Government of State of Orissa is pleased to nominate Shri Gobinda Munda, Deputy Minister for Labour and Health, State of Orissa as Vice-Chairman of the Regional Board for Orissa Region.

Now, therefore, the following amendment is hereby made in the Employees' State Insurance Corporation Notification

No. 2-12(1)/68-Estt. III, dated 29-8-1969 pertaining to the constitution of the Regional Board for Orissa Region, namely :—

In the said notification after item No. 1, the following shall be added with effect from the date of issue of this notification, namely :—

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| "Item No. 1(a) | Shri Gobinda Munda, Deputy Minister for Labour and Health, State of Orissa. | Vice-Chairman; nominated by the Chairman, E.S.I. Corporation." |
|----------------|---|--|

T. C. PURI

*Director General*

